देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित | www.page3news.in | नगर संस्करण वर्ष 16 अंक: 176 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

विचार-प्रवाह...भारत की पहल को सम्मान

पेज थ्री

देहरादून, बृहस्पतिवार, 14 अक्टूबर 2021

मौसम अधिकतम 27.0° न्यूनतम 24.0° | 40243.39

2 अफगानिस्तान को निगल नहीं सकते | 7 टीम इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप जर्सी लान्च

कोयले की आपूर्ति में कोई संकट नहीं

केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने देश को दिया आश्वासन

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

बिलासपुर। कोयले की कमी से जूझ रहे देश के बिजली संयंत्रों के बीच केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को आश्वासन दिया कि बिजली उत्पादन के लिए कोयले की आपूर्ति में कोई संकट नहीं आएगा। जोशी ने बिलासपुर हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद पत्रकारों से बात की। उनका कार्यक्रम पड़ोसी कोरबा जिले जाना का है, जहां वे कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की गेवरा, दीपका और कुसमुंडा खदानों का जायजा लेने गए हैं और वे बाद में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। यह पूछे जाने पर, कांग्रेस कोयले की कमी का दावा कर रही है, इसपर कोयला और खान मंत्री ने कहा, मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता। हम पहले से ही कुल आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आज बिजली उत्पादन के लिए 11 लाख टन कोयले की जरूरत है और हम पहले ही 20 लाख टन कोयले की आपूर्ति कर चुके हैं। इसकी वजह से स्टाक भी चढ़ रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि देश में बिजली उत्पादन के लिए आपूर्ति को पूरा करने में कोई समस्या नहीं होगी।

जोशी ने कहा कि वह एसईसीएल की खदानों का जायजा लेने और वहां उत्पादन में तेजी लाने के लिए चर्चा करने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक आवश्यकता का सवाल है, बिजली मंत्रालय ने 19 लाख टन और 20 (अक्टूबर) के बाद 20 लाख टन की आपूर्ति की मांग रखी थी। आज ही हमने 20 लाख टन की आपूर्ति की है और बाकी चीजों पर मैं (खदानों की) समीक्षा के बाद चर्चा करूंगा।

बता दें कि मंगलवार को, प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कोयला आपूर्ति और बिजली उत्पादन परिदृश्य की समीक्षा की। सरकार के समक्ष कई राज्यों द्वारा ऊर्जा संकट की परेशानी सामने रखी गई है, जिसपर केंद्र सरकार कई तरीकों पर विचार कर रही है।

सूत्रों ने पहले कहा था कि कोयला मंत्रालय को कोयले की आपूर्ति में तेजी लाने के लिए कहा गया है, जबकि रेलवे को ईंधन को बिजली संयंत्रों तक पहुंचाने के लिए रेक उपलब्ध कराने को कहा गया है। कोयले की कमी – जो भारत में बिजली बनाने के लिए लगभग 70 फीसद तक काम आता है– ने राजस्थान से लेकर केरल तक राज्यों में घूर्णी बिजली कटौती को मजबूर किया है।

हरित वित्त पोषण की दरकार

एक अनुमान के मुताबिक विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को तत्काल 100 अरब डालर का हरित कोष मुहैया कराया जाना चाहिए। अमीर देश विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के नाम पर हरित ऊर्जा के बड़े लक्ष्य पूरे होते देखना चाहते हैं, लेकिन वे विकासशील देशों को महंगी हरित ऊर्जा परियोजनाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई का कोई साझा तंत्र विकसित करने में नाकाम हैं।

खनन पर आर्थिक अनिश्चितता का असर

देश में कोयले के कथित संकट को लेकर तरह-तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। कुल बिजली उत्पादन का 70 प्रतिशत हिस्सा कोयला आधारित परियोजनाओं पर निर्भर है। यही वजह है कि कोयला संकट का करंट हर जगह महसूस किया जा रहा है। कुछ राजनीतिक दल तो इसमें पालिटिकल माइलेज भी तलाश रहे हैं। कोयले की आपूर्ति और मांग में अचानक आए अंतर की सबसे अहम वजह कोरोना काल की आर्थिक अनिश्चितता से खनन में आई गिरावट, राज्यों की ओर से लंबित भुगतान और आयातित कोयले की दरों में वृद्धि है।

अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ी मांग

कोरोना काल के बाद भारतीय अर्थतंत्र में बिजली समेत सभी आठ बुनियादी क्षेत्रों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में देश की जीडीपी पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 20.1 प्रतिशत की बढ़त दर्ज कर चुकी है। इस दौरान खनन क्षेत्र में 18.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश में बिजली की खपत अगस्त-सितंबर 2021 में 124.2 अरब यूनिट हुई है, वहीं अगस्त 2019 में यह 106.6 अरब यूनिट थी। कोयले की आपूर्ति में आई तात्कालिक रुकावट को समझने के लिए जरा कोविड काल की परिस्थितियों को याद करें। पहले और दूसरे चरण के लाकडाउन के दौरान देश में बिजली की खपत पिछले कई दशकों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी।

संक्षिप्त समाचार

राष्ट्रपति आज और कल लद्दाख और जम्मू और कश्मीर का करेंगे दौरा

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द 14 और 15 अक्टूबर को लद्दाख और जम्मू और कश्मीर का दौरा करेंगे। 14 अक्टूबर को वह लेह के सिंधु घाट में सिंधु दर्शन पूजा करेंगे और उधमपुर में सैनिकों के साथ बातचीत भी करेंगे। 15 अक्टूबर को वह द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे। राष्ट्रपति भवन ने इसकी जानकारी दी है।

पीएम मोदी ने विभागों में समन्वय न होने के नुकसान गिनाएं

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गतिशक्ति का शुभारंभ किया। पीएम मोदी देश के बुनियादी ढांचे के परिदृश्य के परिवर्तन की दिशा में 100 लाख करोड़ की योजनाओं को हरी झंडी दिखाने के लिए प्रगति मैदान पहुंचे। यह रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला डिजिटल प्लेटफार्म है।

पुनर्वासित परिवारों को मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं

2017 के बाद 81 गांवों के 1436 परिवारों को पुनर्वासित किया गया

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में अन्तरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाय कि पुनर्वासित परिवारों को पुनर्वास क्षेत्र में बिजली, पानी एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पर्याप्त व्यवस्था हो। जिन पुनर्वासित गांवों को सड़क से जोड़ा जाना है, उनकी सूची शासन को उपलब्ध कराई जाय। पुनर्वासित गांवों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए व्यवस्था मनरेगा से कन्वरजेंस एवं जिलाधिकारी के नियंत्रणाधीन विभिन्न फंडों से की जाय। इसके बाद भी कोई परेशानी हो तो मामला शासन स्तर पर लाया जाय।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से आठ जनपदों के पुनर्वासित गांवों के लोगों से बात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी समस्याओं का उचित हल निकालने का प्रयास किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील गांवों का लगातार सर्वे किया जाय। सर्वे के बाद जिन गांवों एवं परिवारों को तत्काल पुनर्वासित करने की आवश्यकता है, उसकी सूची भी जल्द उपलब्ध कराई जाय। पुनर्वासित परिवारों के लिए भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुसार धनराशि दी गई है। पुनर्वासित क्षेत्र में अवस्थापना विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों का कोविड से निधन हुआ उन्हें आपदा मद से 50 हजार रूपये की धनराशि देने की व्यवस्था की जा रही है।

इस अवसर पर आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, सचिव आपदा प्रबंधन एस. ए.मुरुगेशन, वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।

सुप्रीम कोर्ट के दो जज करें जांच: राहुल गांधी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की घटना को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द से मिलने बुधवार को राष्ट्रपति भवन पहुंचा गया। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में हुई हिंसा की घटना को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द से मिला। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और इस मामले में सक्रिय दिख रही प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल दल राष्ट्रपति कोविन्द से मिला और इस घटना से जुड़े तथ्यों के साथ उन्हें एक ज्ञापन सौंपा।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर हमने राष्ट्रपति से कहा कि आरोपी के पिता जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनको पद से हटा देना चाहिए क्योंकि उनकी मौजूदगी में निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। इसी तरह, हमने सुप्रीम कोर्ट के दो मौजूदा जजों से भी जांच कराने की मांग की।

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने राष्ट्रपति को लखीमपुर खीरी कांड के संबंध में सारी जानकारी दी. हमारी 2 मांगें हैं– मौजूदा जजों से स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और गृह राज्य मंत्री (अजय मिश्रा टेनी) को या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या बर्खास्त कर देना चाहिए। न्याय तभी संभव होगा।

कांग्रेस नेताओं की राष्ट्रपति कोविन्द से मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए राष्ट्रपति भवन ने ट्वीट किया– कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, एके एंटनी, गुलाम नबी आजाद, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी थे उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की।

मांग

■लखीमपुर हिंसा मामले पर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा राष्ट्रपति को ज्ञापन

Are you Planning to make a Website or already have ?

If yes, then we are here to serve you

What we do

Website Development: All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.

Promotion & Branding: 1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries) 2. Social Media 3. Bulk SMS

Search Engine Optimisation: A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly. You tell us, we do it.

Contact: **Gadoli Media Ventures**

Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. I Mob: 9319700701, 7579011930

E-Mail: contact@gadoli.in

गिरफ्तार पाक आतंकी का खुलासा

इंडिया गेट, लाल किला, 2011 दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट समेत 10 जगहों की रेकी की थी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को जिस पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ को पकड़ा था, उसने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। सूत्रों ने कहा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल द्वारा मंगलवार को गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद अशरफ ने दिल्ली में कई जगहों की रेकी की थी। आरोपी मोहम्मद अशरफ ने 2011 के दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट से पहले रेकी की थी।

घटनाक्रम से जुड़े करीबी सूत्रों ने एनआईए को बताया कि पूछताछ के दौरान जब 2011 के दिल्ली उच्च न्यायालय विस्फोट में एक आरोपी की तस्वीर दिखाई गई तो उसने खुलासा किया कि उसने उच्च न्यायालय (दिल्ली हाईकोर्ट) की रेकी की थी। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट विस्फोट में उसकी संलिप्तता स्पष्ट रूप से नहीं बताई जा सकती है। आगे की जांच के बाद इसको स्पष्ट किया जाएगा। अभी तक कोई सबूत नहीं हैं। अशरफ से NIA, RAW और MI ने भी लंबी पूछताछ की।